ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 77
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಕಾಂತರಾಜ್ (ಬಿಎಂಎಲ್)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 13.12.2021
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
(ಅ)	ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (State Environment Impact Assessment Authority-Karnataka) ಎಂದರೇನು; ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳೇನು; ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಯಾರ್‍ಯಾರು; (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯಿದೆ, 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Environment Impact Assessment (EIA), ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006 ನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸದರಿ EIA ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006 ರ ಅನುಸಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (State Environment Impact Assessment Authority- Karnataka) ವನ್ನು 2007 ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪುನಾರಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ 'ಬಿ' ವರ್ಗದ ಯೋಜನೆ/ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪರಿಸರ ವಿಮೋಚನಾ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಸ್.ಓ.4170(ಇ), ದಿನಾಂಕ:19.11.2020ರ ಅನ್ವಯ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪುನಾರಚನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-1** ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
(ಆ)	ಪರಿಸರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (Environment Impact Assessment) ಎಂದರೇನು; ಇದನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿ / ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ; (ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಪರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಕಾಯಿದೆ, 1986 ಸೆಕ್ಷನ್ 3ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Environment Impact Assessment (EIA), ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2006 ಅನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು / ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹೊಸ, ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಮಿಶ್ರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪೂರ್ವ ಪರಿಸರ ವಿಮೋಚನಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

(ಇ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪರಿಸರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (Environment Impact Assessment) ಯಡಿ ಎಷ್ಟು ಏಜೆನ್ಸಿ/ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೊಂದಾವಣೆಯಾಗಿದೆ; (ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ನೊಂದಣಿ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚಕರ (Consultant) ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Environment Impact Assessment ಸಂಬಂಧ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು (Consultant) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ National Accreditation Board for Education and Training (NABET) ರವರ ಮುಖೇನ ಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
(ಈ)	ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ? (ವಿಭಾಗವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು)	ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 287 ಇಪಿಸಿ 2021

(ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್)
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು
ಜೀವಿಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಚಿವರು.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112020-223203
CG-DL-E-20112020-223203

xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3 — उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3668] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2020/ कार्तिक 29, 1942
No.3668] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2020/KARTIKA 29, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2020

का.आ. 4170(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण((एसईआईएए),कर्नाटक (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, कर्नाटक कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	डॉ. के. आर. श्री हर्ष, # 5/76, भारती, दूसरी मंजिल, 4 वीं मेन, ओपी महिला मंडली स्कूल, एनआर कॉलोनी, बसवनगुडी, बेंगलुरु -560019	अध्यक्ष ;
2.	श्री के एन शिवलिंग गौडा, नंबर 297, 8 वीं मुख्य बीसीसी लेआउट, चंद्र लेआउट के पास, बेंगलुरु -560040	सदस्य ;

3.	सरकार के प्रमुख सचिव (पारिस्थितिकी और पर्यावरण) वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार, एम एस बिल्डिंग, बेंगलुरु -560001	सदस्य सचिव।

2. प्राधिकरण, कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, कर्नाटक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, कर्नाटक अपने विनिश्चय कर्नाटक राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, कर्नाटक की सहायता के उद्देश्य के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, (एस.ई.ए.सी.) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., कर्नाटक कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

1.	श्री वेणुगोपाल वी, सं. 135, 12 ° बी मेन, 6 "ब्लॉक, राजाजीनगर, बेंगलुरु -560010	अध्यक्ष;
2.	डॉ शेकर एच एस, #302, 3 री "मंजिल कोमटेहल्ली रेलवे के पास, समरतुरी जोड़, विरुपक्षपुरा गेट, थिंड्लू मेन रोड, बैलेरी रोड, बेंगलुरु -97	सदस्य;
3.	डॉ जे बी राज, प्रिंसिपल (सेवानिवृत्त) डीआरएम साइंस कॉलेज, # 1962/1, विनायक सदन, विनायक बादवेने-1 मुख्य, दावणगेरे	सदस्य;
4.	श्री नंद किशोर, # 150, 2 "क्रॉस, सेंट्रल एक्साइज लेआउट, बोपासांड्रा, बेंगलुरु-560094	सदस्य;
5.	डॉ एस के गली, सेवानिवृत्त डीन-फॉरेस्ट्री) यूएएस, धारवाड़ सं. 50, शांतिनिकेतन नगर, धारवाड़ -580008	सदस्य;
6.	श्री वैशाख वी आनंद, सदस्य; ईडब्लू-702, रहेजा रेजीडेंसी, 3रा ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरु-560034	सदस्य;
7.	श्री दिनेश एमसी, # 320, विशाल कृपा, 3 मेन रोड, डी ग्रुप लेआउट, श्रीगंधजा कवलु विश्वनोम पोस्ट, बेंगलुरु -560091	सदस्य;
8.	श्री देवगौड़ा राजू, कृषि निदेशक (सेवानिवृत्त) सं. 42, 3री स्टेज, 4 "ब्लॉक, विश्वेश्वरय्या पार्क के पास, बैंगलोर उत्तर, बसवेश्वरा नगर, बेंगलुरु -560079	सदस्य;

9.	श्री शरणबसवा चंद्रशेखर पिल्ली, अन्नपूर्णा, प्लॉट नं. 1254, सह्याद्री नगर, बुडा सेक्टर 47, बेलागवी -590019	सदस्य;
10.	श्री जे जी कावेरीप्पा, सी603, वेरीविलास, सीआरपीएफ के सामने, डोड्डाबल्लपुरा, मेनरोड, येलहंका, बेंगलुरु -560064	सदस्य;
11.	श्री महेंद्र कुमार एम सी, # 316, 6 "मेन रोड, बीएसके 1 ° स्टेज, श्रीनगर, बेंगलुरु -560050	सदस्य;
12.	श्री बी वी ब्यारा रेड्डी, सम्पदा फार्म गदगी मुख्य सड़क, बोगाधी, मैसूर -570026	सदस्य;
13.	डॉ सर्वमंगला आर पाटिल, विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, प्लॉट नं. 4, से. सं 39/3, नागनहल्ली रोड के पास, कोरंती हनुमान मंदिर के पास, कलबुर्गी -585103	सदस्य;
14.	श्री बी रामसुब्बा रेड्डी, # ए -2 / 14-03, एलीटा प्रोमेनेड अपार्टमेंट, आरबीआई लेआउट के पास, जे पी नगर, 7 "चरण, बेंगलुरु-560078	सदस्य;
15.	विशेष निदेशक (तकनीकी सेल), वन, परिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार एमएस बिल्डिंग, बेंगलुरु -560001	सदस्य सचिव

6. एस.ई.ए.सी., कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. एस.ई.ए.सी., कर्नाटक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. एस.ई.ए.सी., कर्नाटक सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. हित के किसी भी संघर्ष से बचने के लिए, -

(क) प्राधिकरण, कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्य घोषित करें कि वे किस परामर्श संगठन और साथ ही परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं ;

(ख) प्राधिकरण, कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्य एक परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के साथ किसी भी परामर्श या सहयोगी नहीं होंगे का कार्य करें जिसके द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण, कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक द्वारा मूल्यांकन किया जाना है; तथा

(ग) यदि पिछले पाँच वर्षों में, प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों में से किसी ने, परियोजना के प्रस्तावक, के लिए कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक परामर्श सेवाएँ प्रदान की हैं या किसी के लिए ईआईए अध्ययन किया है उस घटना में वे प्राधिकरण, कर्नाटक और एसईएसी, कर्नाटक ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में स्वयं को बैठकों से हटा देंगे।

10. कर्नाटक राज्य सरकार, प्राधिकरण कर्नाटक और एस.ई.ए.सी., कर्नाटक के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

11. प्राधिकरण, कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., कर्नाटक के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता कर्नाटक राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013/16/2007आई.ए.II(I)]

सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2020

S.O. 4170(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette Notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Karnataka (hereinafter referred to as the Authority, Karnataka) comprising of the following Members, namely:—

1.	Dr K. R Sree Harsha, #5/76, Bharathi, 2nd Floor, 4th Main, Opp Mahila Mandali School, NR Colony, Basavanagudi, Bengaluru-560019	Chairman;
2.	Shri K N Shivalinge Gowda, No. 297, 8th Main BCC Layout, Near Chandra Layout, Bengaluru-560040	Member;
3.	Principal Secretary to the Government (Ecology & Environment) Forest, Ecology and Environment Deptt., Government of Karnataka, M S Building, Bengaluru-560001	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Karnataka shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

3. The Authority, Karnataka shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette Notification.

4. The Authority, Karnataka shall take its decisions after the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 of this order for the State of Karnataka.

5. To assist the Authority, Karnataka, the Central Government, in consultation with the State Government of Karnataka, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee (SEAC), Karnataka (hereinafter referred to as SEAC, Karnataka) comprising of the following Members, namely: -

1.	Shri Venugopaql V, No. 135, 12th B Main, 6th Block, Rajajinagar, Bengaluru-560010	Chairman
2.	Dr. Shekar H S, #302, 3rd Floor Samtrupti Aparts, Virupakshspura, Near Kodigehalli Railway Gate, Thindlu Main Road, Ballary Road, Bengaluru-97	Member:
3.	Dr. J B Raj, Principal (Retd) DRM Science College, #1962/1, Vinayaka Sadana, Vinayaka Badavane-I Main, Davanagere	Member:
4.	Shri Nanda Kishore, # 150, 2nd Cross, Central Excise Layout, Boopasandra, Bengaluru-560094	Member:
5.	Dr. S K Gali, Retired Dean –Forestry) UAS, Dharwad No. 50, Shantiniketan Nagar, Dharwad-580008	Member:
6.	Shri Vyshak V Anand, EW-702, Raheja Residancy, 3rd Block, Koremangala, Bengaluru-560034	Member:
7.	Sri Dinesh MC, #320, Vishala Krupa, 3rd Main Road, D Group Layout, Srigandhja Kavalu Viswaneedom Post, Bengaluru-560091	Member:
8.	Shri Devgowda Raju, Director of Agriculture (Retd) No. 42, 3rd Stage, 4th Block, Near Vishweshwarayya Park, Bangalore North, Basaveshwara Nagar, Bengaluru-560079	Member:
9.	Shri Sharanabasava Chandrashekhar Pilli, Annapurna, Plot No. 1254, Sahyadri Nagar, BUDA Sch. 47, Belagavi-590019	Member:
10.	Shri J G Kaveriappa, C603, Veracious Vanivilas, Opp to CRPF, Doddaballapura, Main Road, Yelahanka, Bengaluru-560064	Member:
11.	Shri Mahendra Kumar M C, #316, 6th Main Road, BSK 1st Stage, Srinagara, Bengaluru-560050	Member;
12.	Shri B V Byra Reddy, Sampada Farm Gaddige main Road, Bogadhi, Mysore-570026	Member;
13.	Dr. Sarvamangala R Patil, Vishweshwariah College of Applied Sciences, Plot No. 4, Sy No. 39/3, Naganahalli Road, Near Koranti Hanuman Temple, Kalaburgi-585103	Member:
14.	Sri B Ramasubba Reddy, #A-2/14-03, Elita Promenade Apartment, Near RBI Layout, J P Nagar, 7th Phase, Bengaluru-560078	Member;
15.	Special Director (Technical Cell), Forest, Ecology and Environment Department, Government of Karnataka, MS Building, Bengaluru-560001	Member Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Karnataka shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

7. The SEAC, Karnataka shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette Notification.

8. The SEAC, Karnataka shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest,-

(a) the Chairman and Members of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka shall declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environment Impact Assessment (EIA) and Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Karnataka shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all the statutory functions of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Karnataka and SEAC, Karnataka shall be paid as per the rules of the State Government of Karnataka.

[F. No. J-11013/16/2007-IA-II (I)]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

12. Operation of EIA Notification, 1994, till disposal of pending cases:

From the date of final publication of this notification the Environment Impact Assessment (EIA) notification number S.O.60 (E) dated 27th January, 1994 is hereby superseded, except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression to the extent that in case of all or some types of applications made for prior environmental clearance and pending on the date of final publication of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification except the list of the projects or activities requiring prior environmental clearance in Schedule I , or continue operation of some or all provisions of the said notification, for a period not exceeding twenty four months from the date of issue of this notification.

[No. J-11013/---/2015-IA-II (I)]
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O.695(E) dated the 4th April, 2011, S.O 2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O.674(E) dated the 13th March, 2013, S.O.2204(E) dated the 19th July, 2013, S.O.2555(E) dated the 21st August, 2013, S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 , S.O.637(E) dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014, S.O. 2600 (E) dated 9th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015, S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015, S.O. 996 (E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142 (E) dated 17th April, 2015, S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015 and S.O.1834 (E) dated the 6th July, 2015.

SCHEDULE

(See paragraph 2 and 7)

LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1		Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1(a)	(i)Mining of minerals (ii)Slurry pipelines (coal, lignite and other ores) passing through national parks / sanctuaries / coral reefs, ecologically sensitive areas.	≥ 50 ha. of mining lease area in respect of non-coal mine lease. >150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease Asbestos mining irrespective of mining area All projects.	<50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease. ≤ 150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	General Condition shall apply except for project or activity of less than 5 ha of mining lease area: Provided that the above exception shall not apply for project or activity if the sum total of the mining lease area of the said project or activity and that of existing operating mines and mining projects which were accorded environment clearance and are located within 500 meters from the periphery of such project or activity equals or exceeds 5 ha. Note (i)Prior environmental clearance is required at the stage of renewal of mine lease for which an application shall be made up to two years prior to the date due for renewal. Provided that no fresh environmental clearance shall be required for a mining project or activity at the time of renewal of mining lease, which has already obtained environmental clearance, under this Notification. (ii) Mineral prospecting is exempted.

1(b)	Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production	All projects		Note Seismic surveys which are part of Exploration surveys are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey
1(c)	(i)River Valley projects (ii)Irrigation projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area	(i) < 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation; (ii) < 10,000 ha. > 2000 ha. of culturable command area	General Condition shall apply Note: Irrigation projects not involving submergence or inter-state domain shall be appraised by the SEIAA as Category 'B' Projects. Category 'B' river valley projects falling in more than one state shall be appraised at the central Government Level.
1(d)	Thermal Power Plants	≥ 500 MW (coal/lignite/naptha & gas based); ≥ 50 MW (all other fuels except biomass). >20 MW (using municipal solid non-hazardous waste, as fuel).	>50 MW < 500 MW (coal/lignite/ naptha & gas based); <50 MW ≥ 5MW (all other fuels except biomass and municipal solid non-hazardous waste); <20 MW >15 MW (using municipal solid non-hazardous waste, as fuel). >15 MW plants based on biomass fuel.	General Condition shall apply. Note: (i)Thermal Power Plants up to 15 MW based on biomass or non-hazardous municipal solid waste using auxiliary fuel such as coal, lignite / petroleum products up to 15% are exempt. (ii)Thermal Power plants using waste heat boilers without any auxiliary fuel are exempt.
1(e)	Nuclear power projects and processing of nuclear fuel	All projects	-	
2		**Primary Processing**		

2(a)	Coal washeries	≥ 1 million ton/annum throughput of coal	<1million ton/annum throughput of coal	General Condition shall apply (If located within mining area the proposal shall be appraised together with the mining proposal)
2 (b)	Mineral beneficiation	≥ 0.5 million TPA throughput	< 0.5 million TPA throughput	General Condition shall apply (Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance).

3		**Materials Production**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)	a)Primary metallurgical industry All projects b) Sponge iron manufacturing ≥ 200TPD c)Secondary metallurgical processing industry All toxic and heavy metal producing units ≥ 20,000 tonnes /annum -	Sponge iron manufacturing <200TPD Secondary metallurgical processing industry i.)All toxic and heavy metal producing units <20,000 tonnes /annum ii.)All other non –toxic secondary metallurgical processing industries >5000 tonnes/annum	General Condition shall apply. Note: (i)The recycling industrial units registered under the HSM Rules are exempt. (ii)In case of secondary metallurgical processing industrial units, those projects involving operation of furnaces only such as induction and electric arc furnace, and cupola with capacity more than 30000 tonnes per annum (TPA) would require environmental clearance. (iii)Plant / units other than power plants (given against entry no. 1(d) of the schedule), based on municipal solid waste (non-hazardous) are exempted.
3(b)	Cement plants	≥ 1.0 million tonnes/annum production capacity	<1.0 million tonnes/annum production capacity. All Stand alone grinding units	General Condition shall apply
4		**Materials Processing**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4(a)	Petroleum refining industry	All projects	-	-

4(b)	(i)Coke oven plants (ii) Coaltar processing units	≥2,50,000 tonnes/annum	<2,50,000 & ≥25,000 tonnes/annum All projects	General conditions shall apply
4(c)	Asbestos milling and asbestos based products	All projects	-	-
4(d)	Chlor-alkali industry	≥300 TPD production capacity if a unit located out side the notified industrial area/ estate	(i)All projects irrespective of the size, if it is located in a Notified Industrial Area / Estate. <300 tonnes per day (TPD) and located outside a Notified Industrial Area / Estate.	General as well as specific conditions shall apply No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempted from the Notification.
4(e)	Soda ash Industry	All projects	-	-
4(f)	Skin/hide processing including tanning industry	New projects outside the industrial area or expansion of existing units out side the industrial area	All new or expansion of projects located within a notified industrial area/ estate	General as well as specific conditions shall apply
5		**Manufacturing/Fabrication**		
5(a)	Chemical fertilizers	All projects including all Single Super Phosphatc with H_2SO_4 production except granulation of chemical fertilizers.	All Single Super Phosphate without H_2SO_4 production and granulation of chemical fertilizers	General condition shall apply. Granulation of single super phosphate powder is exempt.
5(b)	Pesticides industry and pesticide specific intermediates (excluding formulations)	All units producing technical grade pesticides	-	-
5(c)	Petro-chemical complexes (industries based	All projects -	-	-

	on processing of petroleum fractions & natural gas and/or reforming to aromatics)			
5(d)	Manmade fibres manufacturing	Rayon	Others	General Condition shall apply
5(e)	Petrochemical products and petrochemical based processing such as production of carbon black and electrode grade graphite (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes).	Located out side the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/ estate	General as well as specific conditions shall apply. Note: Manufacturing of products from polymer granules is exempt.
5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	Located out side the notified industrial area/ estate except small units as defined in column (5)	(i)Located in a notified industrial area/ estate. (ii)Small units as defined in column (5)	General as well as specific conditions shall apply. Small units: with water consumption <25 cu mt per day, fuel consumption <25 TPD and not covered in the category of MAH units as per the Management, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.
5(g)	Distilleries	(i)All Molasses based distilleries (ii) Non-molasses based distilleries ≥60 KLD	Non-molasses based distilleries – <60 KLD	General Condition shall apply

5(h)	Integrated paint industry	-	All projects	General Condition shall apply
5(i)	Pulp & paper industry	Pulp manufacturing and Pulp & Paper manufacturing industry except from waste paper	Pulp manufacturing from waste paper and paper manufacturing from waste paper pulp and other ready pulp	General Condition shall apply. Note: Paper manufacturing from waste paper pulp and ready pulp without deinking, bleaching and colouring is exempt.
5(j)	Sugar Industry	- -	≥ 5000 tcd cane crushing capacity	General Condition shall apply
6		**Service Sectors**		
6(a)	Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks /sanctuaries/coral reefs /ecologically sensitive areas including LNG Terminal	All projects		-
6(b)	Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000)	-	All projects	General Condition shall apply
7		**Physical Infrastructure including Environmental Services**		

7(a)	Air ports	All projects including airstrips, which are for commercial use	-	Air strips which do not involve bunkering / refueling facility and or Air Traffic Control, are exempted.
7(b)	All ship breaking yards including ship breaking units	All projects	-	-
7(c)	Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes.	If at least one industry in the proposed industrial estate falls under the Category A, entire industrial area shall be treated as Category A, irrespective of the area. Industrial estates with area greater than 500 ha. and housing at least one Category B industry.	Industrial estates housing at least one Category B industry and area <500 ha. Industrial estates of area> 500 ha. and not housing any industry belonging to Category A or B.	General as well as specific conditions shall apply Note: 1.Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance. 2.If the area is less than 500 ha. But contains building and construction projects > 20000 sq. mtr. and or development area more than 50 ha it will be treated as activity listed at serial no. 8(a) or 8(b) in the Schedule, as the case may be.
7(d)	Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)	All integrated facilities having incineration & landfill or incineration alone	All facilities having land fill only	General Condition shall apply
7(da)	Bio-Medical Waste Treatment Facilities	-	All projects	-
7(e)	Ports, harbors, break waters, dredging	≥ 5 million TPA of cargo handling capacity (excluding fishing harbours)	< 5 million TPA of cargo handling capacity and/or ports/ harbours ≥10,000 TPA of fish handling capacity	General Condition shall apply Note: 1.Capital dredging inside and outside the ports or harbors and channels are included; 2.Maintenance dredging is exempt provided it formed part of the original proposal for which Environment

				Management Plan (EMP) was prepared and environmental clearance obtained.
7(f)	Highways	i) New National High ways; and ii) Expansion of National High ways greater than 100 km involving additional right of way or land acquisition greater than 40m on existing alignment and 60 m on re-alignment or by-passes	i) All New State Highway Projects; ii) State Highway expansion projects in hilly terrain (above 1000 m AMSL) and or ecologically sensitive areas.	General Condition shall apply Note: Highways include expressways.
7(g)	Aerial ropeways	(i)All projects located at altitude of 1000 mtr. and above; (ii)All projects located in notified ecologically sensitive areas.	All projects except those covered in column (3).	General Condition shall apply
7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)		All projects	General Condition shall apply
7(i)	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)		All projects	General Condition shall apply
8		**Building or Construction projects or Area Development projects and Townships**		
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of built up area	The term "built up area" for the purpose of this Notification the built up or covered area on all the floors put together including its basement and other service areas, which

				are proposed in the building or construction projects. **Note 1.-** The projects or activities shall not include industrial shed, school, college, hostel for educational institution, but such buildings shall ensure sustainable environmental management, solid and liquid waste management, rain water harvesting and may use recycled materials such as fly ash bricks. **Note-2.-** "General Conditions" shall not apply.
8(b)	Townships and Area Development projects.		Covering an area of > 50 ha and or built up area > 1,50,000 sq .mtrs	A project of Township and Area Development Projects covered under this item shall require an Environment Assessment report and be apprised as Category 'B1' Project. **Note.-** "General Conditions" shall not apply.

Note:-

General Condition (GC):

Any project or activity specified in Category 'B' will be appraised at the Central Level as Category 'A', if located in whole or in part within 5 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial Estates/ parks/complexes/areas, Export Processing Zones (EPZ), Special Economic Zones (SEZs),

biotech parks, leather complexes specified in item 7 (c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7 (d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10 km.

Provided further that the requirement regarding distance of 5 km or 10 km, as the case may be, of the inter-State boundaries can be reduced or completely done away with by an agreement between the respective States or the Union Territories sharing the common boundary in case the activity does not fall within 5 km or 10 km, as the case may be of the areas mentioned at item (i), (ii), and (iii) above.

Specific Condition (SC):

If any Industrial Estate/Complex / Export processing Zones /Special Economic Zones/Biotech Parks / Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre –defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates /complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/estate).

21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 ;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 ;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 ;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015,
25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015,
26. का.आ. 141(अ) 15 जनवरी, 2016,
27. का.आ. 648(अ) तारीख 3 मार्च, 2016 ;
28. का.आ. 2269(अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 ;
29. का.आ. 2944(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2016;
30. का.आ. 3518(अ), तारीख 23 नवंबर, 2016 ;
31. का.आ. 3999(अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का.आ. 4241(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2016; और
33. का.आ. 3611(अ), तारीख 25 जुलाई, 2018 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2018

S.O. 3977(E).— Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing capacity addition with change in process or technology or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the said Ministry has received requests, for delegation of more powers to State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) and District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) with respect to grant of Environment Clearances;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas, a draft notification for making amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published, vide number S.O.3933 (E) dated the 18th December 2017, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of said notification in the Gazette of India;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 18th December 2017;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:-

In the said Notification, in the SCHEDULE, for item 1(a), 1(c), and the Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation in Appendix-XI and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:

Project or Activity		Category with threshold limit		*Conditions if any*
		A	B	
1		Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (a)	(i) Mining of minerals (ii)Slurry pipelines (coal, lignite and other ores) passing through national parks / sanctuaries / coral reefs, ecologically sensitive areas.	> 100 ha. of mining lease area in respect of non-coal mine lease. > 150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease Asbestos mining irrespective of mining area. All projects.	≤ 100 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease. ≤ 150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	General Conditions shall apply except: (i) for project or activity of mining of minor minerals of Category 'B2' (up to 25 ha of mining lease area); (ii) for project or activity of mining of minor minerals of Category 'B1' in case of cluster of mining lease area; and (iii) River bed mining projects on account of inter-state boundary. Note: (1) Mineral prospecting is exempted; (2) The prescribed procedure for environmental clearance for mining of minor minerals including cluster situation is given in Appendix XI;
1(c)	(i) River Valley projects (ii) Irrigation projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 50,000 ha. of culturable command area	(i) ≥ 25 MW and < 50 MW hydroelectric power generation; (ii) > 2000 ha. and < 50,000 ha. of culturable command area. **Irrigation system** — **Requirement of EC** (a) Minor Irrigation system (≤ 2000 Ha) — Exempted (b) Medium irrigation system (> 2000 and < 10,000 ha.) — Required to prepare EMP and to be dealt at State Level (B_2 category).	General Condition shall apply. Note:- (i) Category 'B' river valley projects falling in more than one state shall be appraised at the central Government Level. (ii) Change in irrigation technology having environmental benefits (eg. From flood irrigation to Drip irrigation etc.) by an existing project, leading to increase in Culturable Command Area but without increase in dam height and submergence, will not require amendment/ revision of EC.

			(c) Major irrigation system (≥10,000 to < 50,000 ha.)	Required to prepare EIA/EMP and to be dealt at State Level (B_1 category).	

Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation in Appendix-XI:

Area of Lease (Hectare)	Category of Project	Requirement of EIA / EMP/ DSR	Requirement of Public Hearing	Requirement of EC	Who can prepare EIA/ EMP	Who will apply for EC	Authority to appraise/ grant EC	Authority to monitor EC compliance
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining on the basis of individual mine lease								
0 – 5ha	'B2'	Form –1M, PFR, DSR and Approved Mine Plan	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
> 5 ha and < 25 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EMP	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	
≥ 25ha and ≤ 100ha	'B1'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EIA and EMP	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	
> 100 ha	'A'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EIA and EMP	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining in cluster situation								
Cluster area of mine leases up to 5 ha	'B2'	Form –1M, PFR, DSR and Approved Mine Plan	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with no individual lease > 5 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with any individual lease > 5 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	

Cluster of mine leases of area ≥ 25 hectares with individual lease size ≤ 100ha	'B1'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EIA/EMP forall leases in the Cluster	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	
Cluster of any size with any of the individual lease > 100ha	'A'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EIA/EMP for all leases in the Cluster	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	

[F. No. 19-2/2013-IA.III (Pt.II)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;

19. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का.आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का.आ. 648(अ), तारीख 03 मार्च, 2016;
28. का.आ. 2269(अ), तारीख 01 जुलाई, 2016;
29. का.आ. 2944(अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का.आ. 3518(अ), तारीख 23 नवंबर, 2016;
31. का.आ. 3999(अ), तारीख 09 दिसंबर, 2016;
32. का .आ. 4241 (अ) , तारीख़ 30 दिसंबर,2016;
33. का.आ. 3611(अ), तारीख 25 जुलाई, 2018;
34. का.आ. 3977(अ), तारीख 14 अगस्त, 2018;
35. का.आ. 5733(अ), तारीख 14 नवंबर, 2018;
36. का.आ. 5736(अ), तारीख 15 नवंबर, 2018;
37. का.आ. 5845(अ), तारीख 26 नवंबर, 2018; और
38. का.आ. 345(अ), तारीख 17 जनवरी, 2019.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2019

S.O. 1960(E).—Whereas, a draft notification further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest vide number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 was published in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 *vide* S.O. 387(E), dated the 24th January, 2019, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of the said notification in the Gazette of India;

Whereas, all objections and suggestions received in response to the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

And whereas, there is a need for rationalising and expediting the environment clearance for distilleries and ethanol storage in view of the emphasis on increasing production of biofuels to meet the target of 20 percent blending with petrol by the year of 2030 without compromising the environmental safeguards.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, hereby makes the following further amendments in the said notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:—

In the said notification, in the SCHEDULE—(a) For item 5(g), and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

Project/ Activity	Category with threshold limit		Conditions, if any
	A	B	
5	Manufacturing/Fabrication		
"5(g) Distilleries	Molasses based distilleries > 100 KLD Non-molasses based distilleries >200 KLD	Molasses based distilleries ≤ 100 KLD Non-molasses based distilleries≤ 200 KLD	General Condition shall apply";

(b) Item 6(b) and the entries relating thereto shall be omitted.

[F No.IA-J-11013/55/2017.IA.II(I) pt]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:—

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;

15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E) dated the 14th August, 2018
35. S.O. 5733 (E) dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E) dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E) dated the 26th November, 2018; and
38. S.O. 345(E) dated the 17th January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.